JANSATTA, Delhi, 24.11.2022
Page No. 21, Size:(7.00)cms X (8.39)cms.

कड़े कानून मानवाधिकार छीनने के लिए नहीं : अरुण मिश्रा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 नवंबर।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा है कि यूएपीए जैसे विशेष कानून मानवाधिकारों को छीनने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में आवश्यक बल प्रयोग की आवश्यकता को मानव धर्म के भारतीय चिंतन में भी स्वीकार किया गया है। मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन भारतीय संस्कृति, दर्शन और व्यवहार का अहम हिस्सा है। ऋगवेद काल से ही प्राचीन भारतीय सभ्यता में इसकी परंपरा रही है।

रामायण काल में भी राम ने लक्ष्मण को जरूरत के मुताबिक ही बल प्रयोग करने को कहा था। लड़ाई में भीषण नरसंहार के लिए नहीं कहा था। आयोग की तरफ से केंद्रीय सशस्त्र बलों की 27वीं वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने बुधवार को सुरक्षा बलों के उचित बल प्रयोग को वाजिब ठहराया। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय मूल्य लोगों को प्रकृति के सभी तत्वों की रक्षा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए भी यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की भूमिका देश की एकता और अंखडता की रक्षा करना है और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रतियोगिता में सीआइएसएफ ने अव्वल रहकर ट्राफी जीती। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में आयोग के सदस्यों डीएम मुले व राजीव जैन और महासचिव डीके सिंह भी मौजूद थे। आयोग के अन्वेषण महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन का विचार मानवाधिकारों के संरक्षण व कानून के शासन के तहत सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करना है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा है कि यूएपीए जैसे विशेष कानून मानवाधिकारों को छीनने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे।

जनसत्ता Thu, 24 November 2022
https://epaper.jansatta.com/c/70947217

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 24.11.2022
Page No. 7, Size:(4.03)cms X (5.38)cms.

यूएपीए जैसे कानून मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए : एनएचआरसी प्रमुख

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे कुछ विशेष कानून मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं न कि उन्हें छीनने के लिए। वह यहां सीआईएसएफ के सहयोग से आयोजित सीएपीएफ के लिए एनएचआरसी की 27वीं वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। एनएचआरसी द्वारा जारी एक बयान में मिश्रा के हवाले से कहा गया, 'यूएपीए जैसे कुछ विशेष कानून मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए थे न कि उन्हें छीनने के लिए।'

उन्होंने कहा कि प्रतिकूल हालात से निपटने में शक्ति का इस्तेमाल करने की अवधारणा 'मानव धर्म' के भारतीय विचार में अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण भारतीय संस्कृति, दर्शन और अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय शास्त्रों में ऋग्वेद के ठीक बाद हुई है।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Delhi, 24.11.2022
Page No. 3, Size:(8.63)cms X (3.43)cms.

प्रतियोगिता में सीआइएसएफ की टीम सर्वश्रेष्ठ

जासं, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में सीआइएसएफ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार बीपीआरएंडडी मुख्यालय में 27वीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सीआइएसएफ की टीम ने ओवर आल सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग ट्राफी जीती। सेमीफाइनल राउंड का आयोजन 15 नवंबर को सीआइएसएफ केआरटीसी मुंडली (ओडिसा) में किया गया जिसमें 31 टीमों ने भाग लिया था। 31 टीमों में से 08 फाइनल राउंड में पहुंची। इसमें सभी अन्य प्रतिभागियों को मात देते हुए अंग्रेजी भाषा में प्रथम उप निरीक्षक नजीश खान, द्वितीय उप कमांडेंट मेहुल शिंदे और तृतीय उप कमांडेंट राघवेंद्र सिंह रहे। इससे पूर्व वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक सीआइएसएफ लगातार सात बार ओवर आल सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग ट्राफी विजेता रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा में मानवाधिकारों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 24.11.2022
Page No. 1, Size:(10.81)cms X (10.86)cms.

मेघालय में असम नंबर वाली गाड़ियों पर हमला, बढ़ा तनाव

असम में हुई फायरिंग में मेघालय के पांच लोगों की मौत के बाद भारी रोष

■ पीटीआई, गुवाहाटी

असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को हुई हिंसा में मेघालय के पांच लोगों और असम के एक फॉरेस्ट गार्ड की मौत के बाद दोनों पड़ोसी राज्यों में तनाव बढ़ गया है। मेघालय में असम के वाहनों पर हमलों की खबर के बाद असम पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वाहन मालिकों से पड़ोसी राज्य में जाने से बचने को कहा है। वहीं मेघालय के ग्रामीणों के एक समूह ने बुधवार को वन विभाग के एक कार्यालय पहुंचकर तोड़फोड़ और आगजनी की।

बता दें कि असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में असम-मेघालय सीमा पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार तड़के रोकने के बाद भड़की हिंसा में एक फॉरेस्ट गार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई।

घटना में अपने लोगों की मौत के बाद मेघालय सरकार सक्रिय हो गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री सी के संगमा ने कहा है कि उनकी अगुआई में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल असम के साथ लगती सीमा पर हुई हिंसा की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने की मांग करने के लिए 24 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। संगमा ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से भी मुलाकात करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटना पर रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने असम के सीएम से फोन पर बात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

वहीं सीमा पर हुई हिंसा में छह लोगों की मौत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए और संयम दिखा सकती थी। इसका असम-मेघालय सीमा मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। देर शाम सीएम सरमा ने बताया कि असम सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और सीबीआई या एनआईए जांच कराने का आग्रह किया है।

माहौल में तनाव के बाद मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग से लौट रहे असमी लोगों को असम सीमा तक पहुंचने के लिए मेघालय नंबर की गाड़ियों से आना पड़ा।

लोगों में गुस्सा, वन विभाग का दफ्तर फूंका

मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले के मुकरोह गांव के लोगों ने मंगलवार रात अंतरराज्यीय सीमा पर असम में खेरोनी वन रेंज के तहत आने वाले एक बीट कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। वहां रखे दस्तावेजों और कई मोटरसाइकिल पर भी आग लगा दी।

NAVBHARAT TIMES, Faridabad, 24.11.2022
Page No. 1, Size:(8.41)cms X (12.69)cms.

रेप के आरोपी सब-इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई या नहीं?

■ नगर संवाददाता, फरीदाबाद

पति को जेल से छुड़वाने में मदद करने के नाम पर महिला से रेप किया गया। एक पुलिसवाले पर यह आरोप लगने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने डीजीपी और मुख्य सचिव को छह हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने हरियाणा पुलिस से पूछा है कि आरोपी सब-इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। रिपोर्ट में आरोपी एसआई के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की स्थिति पर जानकारी भी मांगी है। आयोग ने लोकसेवकों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। आयोग ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि नीमका जेल में पीड़ित महिला के पति को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले की जांच कर आठ हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भेजें।

लिया संज्ञान

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा
- पीड़िता को कोर्ट में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वकील देने का भी निर्देश

लाइनहाजिर है आरोपी

■ **केस दर्ज** होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार को लाइनहाजिर कर दिया था। आरोप है कि उसने महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया है। महिला की अश्लील फोटो और विडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। आरोप है कि उन्होंने ब्लैकमेल करके महिला से पैसे भी वसूले हैं। मामले में सेक्टर-16 महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।

PTI/ Devdiscourse/ ThePrint/ Latestly/ The Week/ NYOOOZ

CISF declared winner of NHRC debate competition

https://www.ptinews.com/news/national/cisf-declared-winner-of-nhrc-debate-competition/2/463986.html

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2262937-cisf-declared-winner-of-nhrc-debate-competition

https://theprint.in/india/cisf-declared-winner-of-nhrc-debate-competition/1232352/

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-cisf-declared-winner-of-nhrc-debate-competition-4497999.html

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2022/11/23/des72-cisf-debate-human-rights.html

https://www.nyoooz.com/news/delhi/1706348/cisf-declared-winner-of-nhrc-debate-competition/

The Central Industrial Security Force (CISF) was on Wednesday adjudged the overall winner of the 27th CAPF debate competition organised by the National Human Rights Commission (NHRC), according to an official statement.

The competition was held on the topic of "Maintenance of human rights is the primary pre-requisite for rule of law and constitutional governance".

"The CISF team secured maximum marks during the debate and won the overall best team rolling trophy. Since 2014, the CISF has won the overall best team rolling trophy for seven consecutive years till 2020," a spokesperson of the force said.

CISF Director General Sheel Vardhan Singh has congratulated the winners, he added.

The debate competition is organised annually by the NHRC and officers and personnel from the Central Armed Police Forces, such as the CISF, BSF, CRPF, SSB and ITBP, apart from the NSG, Assam Rifles and NDRF, participate in it.

The CISF functions under the Union home ministry. It has a sanctioned strength of about 1.63 lakh personnel and is primarily deployed to guard major civil airports and vital installations of the country in the nuclear, aerospace and other domains.

PTI/ Deccan Herald/ ThePrint/The Week/Devdiscourse/NYOOOZ

Special laws like UAPA were enacted to protect human rights ...

https://www.ptinews.com/news/national/special-laws-like-uapa-were-enacted-to-protect-human-rights-not-take-them-away-nhrc-chief/463989.html

https://www.deccanherald.com/national/special-laws-like-uapa-were-enacted-to-protect-human-rights-not-take-them-away-nhrc-chief-1165161.html

https://theprint.in/india/special-laws-like-uapa-were-enacted-to-protect-human-rights-not-take-them-away-nhrc-chief/1232404/

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2022/11/23/des73-nhrc-mishra.html

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2262944-special-laws-like-uapa-were-enacted-to-protect-human-rights-not-take-them-away-nhrc-chief

https://www.nyoooz.com/news/delhi/1706350/special-laws-like-uapa-were-enacted-to-protect-human-rights-not-take-them-away-nhrc-chief/

NHRC chairperson justice (retd) Arun Kumar Mishra on Wednesday said that some special laws like the Unlawful Activities (Prevention) Act were enacted to protect human rights and not to take them away.

He was addressing a gathering at the 27th NHRC Annual Debate Competition for the Central Armed Police Forces (CAPFs) organised in collaboration with the CISF here. "Some special laws like the UAPA were enacted to protect human rights and not to take them away," he was quoted as saying in a statement issued by the NHRC.

The concept of using proportionate force in dealing with an adversary has been embedded in the Indian idea of "Manav Dharma". The promotion and protection of human rights is a valued part of Indian culture, philosophy, and practice having the genesis in ancient Indian scriptures right since the 'Rig Veda', he said.

This was reflected in the Ramayana period when Lord Ram advised Laxman to use proportionate force and not a weapon of mass destruction during the war, and even in the Mahabharata period, when the warriors fought on principles and after the sunset visited the opposite camps to care of the wounded, the NHRC chief said.

Ancient Indian values guide people to protect and promote all elements in nature, which are so essential for life on the earth. Technology bereft of morals will be destructive to the environment and therefore, life on the earth, he asserted.

He lauded the role of the armed forces in protecting the security and integrity of the nation and providing safety to the citizens braving adverse situations.

Referring to the topic of the debate competition -- 'Maintenance of Human Rights is the primary pre-requisite for rule of law and constitutional governance' -- the NHRC chairperson said though it was more challenging for those who spoke against the motion, the arguments given by the participants for and against the motion indicate their sensibility and understanding, of the respect human rights require to be given during their operations, which is the aim of this debate competition for Central Armed Police Forces.

The CISF lifted the overall best team rolling trophy, winning the final round of the debate competition in Hindi and English.

Among the individual honours, the first prize for debate in Hindi went to Sub Inspector, Vikesh Timande, RPF, and in English to Sub Inspector, Nazish Khan, CISF. Besides the certificates and a memento, the first, second, and third prize winners were also given cash awards of Rs 12,000, Rs 10,000 and Rs 8,000 each respectively, the NHRC said in the statement.

NHRC seeks ATR on death on a joyride swing

https://www.thestatesman.com/cities/bhubaneshwar/nhrc-seeks-atr-on-death-on-a-joyride-swing-1503133444.html

The National Human Rights Commission (NHRC) sought Action Taken Reports (ATRs) from Bolangir District Collector and Superintendent of Police over the electrocution of a man in a joyride swing.

Responding to a petition filed by Rights Activist and Supreme Court Advocate Radhakanta Tripathy, the NHRC issued notice and sought for Action Taken Reports from all the authorities within four weeks.

Debraj Sahu had fallen from a swing of a joyride at a fair in Tureikela block of Balangir district on 8 November last.

The petition alleged that the fatal accident could have been averted if the local authorities had issued a safety certificate after proper inspection of the joyride.

The petition sought for an inquiry and initiation of action against errant officials to check such fatal mishaps in future. The petition also sought for adequate compensation to the next of kin of the deceased.

“The Commission directs its Registry to transmit the copy of complaint to the concerned authority calling for an action taken report within four weeks. The concerned authorities shall also intimate the Commission, if any notice, order etc., has been received by him/them in the instant matter from the State Human Rights Commission? If yes, a copy of such order be also sent to the Commission within four weeks.” The NHRC stated.

NHRC notice to Raj over deaths of workers at city sewage plant

https://m.timesofindia.com/city/jaipur/nhrc-notice-to-raj-over-deaths-of-workers-at-city-sewage-plant/amp_articleshow/95701241.cms

The national human rights commission (NHRC) has sent notices to the state government, the DGP and the chairman of the Jaipur Development Authority over reports of the death of three workers while carrying out repairs in a sewage treatment plant. The NHRC took suo motu cognizance of a media report that two labourers died while conducting repairs of a leaking valve in a 25 feet-deep well of a sewage treatment plant of Jaipur Development Authority (JDA) in Kalwar area on November 18. The third worker died while being treated at a city hospital on Monday. The commission, while appreciating the commendable work done by police officers in pulling out one of the victims from the sewerage well, was of the view that prosecution against the responsible persons or agency, whether public or private, is mandatory under Section 304A of the IPC, who engaged the victims in hazardous cleaning without safety gear, the statement said. Accordingly, the NHRC has issued notices to the chief secretary and the DGP as well as the JDA chairman seeking a report within four weeks, it said. The chief secretary has been asked to intimate whether any relief or rehabilitation has been provided to the family of the deceased. She has also directed to intimate whether the advisory issued by the commission is being implemented, it added. The DGP is expected to inform about the present status of the FIR registered in the matter and action taken against the responsible officers or agencies.

“The JDA has been asked to submit report about the initiation of disciplinary action against errant public servant(s) under relevant service rules, due to whose culpable negligence three precious human lives were lost for not having been provided with the safety equipment,” the rights body said. “According to the media report, there was a complaint of leakage and the victims, who were cousins, were deputed to attend the work without providing any safety equipment to them. The well is reportedly 25-feet-deep in which the victims had entered to undertake the work and when they were trying to tighten the valve of the mainline, it broke, resulting in the sudden flow of the sewage garbage which flooded the well and both the victims came under it,” the statement said. The NHRC had issued an advisory on September 24, 2021 about the ‘Protection of Human Rights of the Persons Engaged in Hazardous Cleaning’ to the Centre, state governments and local authorities with an object to ensure complete eradication of this unhygienic practice. In the advisory, it is specifically mentioned that in case of any sanitary work or hazardous clearing work, the local authority and the contractor or employers are to be held responsible and accountable, jointly and severally, irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary workers

NHRC notice to Rajasthan over deaths of workers at Jaipur sewage plant

https://www.dnpindia.in/states/rajasthan/nhrc-notice-to-rajasthan-over-deaths-of-workers-at-jaipur-sewage-plant/131092/

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Chief Secretary (CS) and Director General of Police (DGP) of Rajasthan and the Jaipur Development Authority (JDA) chairman, seeking a report within four weeks on the death of workers in a sewerage well.

The NHRC said in a statement that the chief secretary has been directed to inform whether the advisory issued by the commission is being implemented by the state of Rajasthan. The DGP has been asked to inform about the present status of the FIR registered in the matter and the action taken against the responsible officers/agencies. The commission would also like to know the health status of the third victim, who is reportedly undergoing treatment at a hospital.

Complaint of sewage leakage

The Jaipur Development Authority chairman has been asked to submit a report regarding initiation of disciplinary action against errant public servants under the relevant service rules, whose negligence led to the loss of two lives by not providing safety equipment. As per media reports, there was a complaint of sewage leakage and the victims, who were cousins, were allegedly deputed to attend the work without providing them any safety equipment.

The well is reportedly 25 feet deep into which the victims had entered to work and when they were trying to tighten the mainline valve, it ruptured, resulting in a sudden gushing of sewage waste that flooded the well and Both the victims got hit by it.

Commission took suo motu cognizance

The Commission took suo motu cognizance of a media report that two laborers died while repairing a leaking valve in a 25 feet deep well of a sewerage treatment plant of Jaipur Development Authority in Kalwad area in Rajasthan on November 18. Reportedly, one of his companions was rescued by a police officer by jumping into the well. He is being provided medical treatment at a hospital, he added. The Commission expressed grave concern that it is constantly pushing the authorities to get such hazardous work done with the help of machines, but it is being done manually without protective equipment, resulting in accidents in various parts of the country. Loss of life and property is happening almost on a daily basis.

Delhi Pollution: Slight respite for Delhiites as AQI improves to moderate category

https://www.timesnownews.com/delhi/delhi-pollution-slight-respite-for-delhiites-as-aqi-improves-to-moderate-category-article-95723270

The overall air quality in the national capital slightly improved to 'moderate' category zone on Thursday morning. The average Air Quality Index (AQI) was recorded at 173, according to the System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR). Around the same time on Wednesday, the index was recorded at 201, falling in the 'poor' category.

Temperature is expected to drop further in Delhi on Sunday. The minimum temperature in the city is likely to be between 9-10 degree Celsius and the maximum will be around 27 degree Celsius. Shallow fog is likely to cover the city in the morning and the sky will remain partly cloudy later, the India Meteorological Department (IMD) said.

recommended by

In Pusa, the AQI was 169, while in the Airport region it touched 150. For Mathura Road, it was 233. The air quality index in the IIT Delhi region was recorded at 142 and atLodhi Road it was 159.

An AQI between 101 and 200 is considered 'moderate', 201 and 300 'poor', 301 and 400 'very poor', and 401 and 500 'severe'.

However, the air quality in Delhi might deplete again on Thursday with an estimated AQI at 232, according to SAFAR.

Meanwhile, The National Human Rights Commission (NHRC) on Saturday held a third round of meetings with the chief secretaries of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh and asked them to submit a detailed report on how to prevent air pollution in the Delhi-NCR region before November 25.

Suvendu meets governor separately at Raj Bhavan

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/suvendu-meets-governor-separately-at-raj-bhavan/articleshow/95727921.cms

: Led by CM Mamata Banerjee, Trinamool Congress seniors were present in full strength at the oath-taking ceremony of new Bengal governor C V Ananda Bose at the Raj Bhavan on Wednesday but leader of opposition Suvendu Adhikari gave the ceremony a miss, taking umbrage at the seating arrangement. Adhikari's seat was towards the rear of the Throne Room between chairs marked for MLAs Krishna Kalyani and Biswajit Das, who joined Trinamool at events outside the assembly after winning the 2021 polls on BJP tickets. "It is not possible for me to take a seat next to such objectionable persons. I have requested the governor to give me an appointment separately," he said, calling what happened "uncultured". He later called on the governor at Raj Bhavan and presented him with a copy of the National Human Rights Commission report on post-poll violence, which Trinamool had junked as being highly partisan, and a copy of the Gita in English. "I sent a welcome mail at 10.50am. He gave me an appointment at 12.45 pm. I reached Raj Bhavan at 12.37 pm and the governor spent 22 minutes with me," he said. The governor, soon after taking oath, got a letter from state Congress president Adhir Chowdhury, complaining of "administrative excesses" on Congress councillors in Purulia's Jhalda Municipality after Trinamool recently lost the board. He sought Bose's intervention because he suspected that efforts were on to appoint an administrator. Bose referred to his "emotional connect" with Kolkata after the ceremony and reminisced how he used to stay near the Shyambazar five-point crossing during his stint here as a State Bank of India probationary officer. One of the stories that Bose has authored is about a flower seller in Kolkata who earned by picking flowers from a cemetery.

UAPA: एनएचआरसी प्रमुख ने यूएपीए को लेकर दिया बड़ा बयान, सशस्त्र बलों की भी सराहना की

https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-chief-says-special-laws-like-uapa-were-enacted-to-protect-human-rights-not-take-them-away

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को यूएपीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे कुछ विशेष कानून मानवाधिकारों को छीनने के लिए नहीं बनाए गए हैं। बल्कि ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हैं। उन्होंने सीआईएसएफ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एनएचआरसी की 27वीं वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता में ये बयान दिया।

एनएचआरसी ने इस बाबत एक बयान भी जारी किया। एनएचआरसी प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने इस कार्यक्रम में कहा कि एक विरोधी से निपटने में आनुपातिक बल का उपयोग करने की अवधारणा "मानव धर्म" के भारतीय विचार में अंतर्निहित है। मानव अधिकारों का प्रचार और संरक्षण भारतीय संस्कृति, दर्शन और अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय शास्त्रों में 'ऋग्वेद' के ठीक बाद से हुई है। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि रामायण काल में भी यह विचार सामने आया। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार के बजाय आनुपातिक बल का उपयोग करने की सलाह दी थी। ऐसा ही महाभारत काल में भी सिद्धांतों के आधार पर युद्ध लड़े जाते थे।

अपने संबोधन में एनएचआरसी प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि प्राचीन भारतीय मूल्य लोगों को प्रकृति में सभी तत्वों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। नैतिकता से रहित प्रौद्योगिकी पर्यावरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी होगी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की भी सराहना की।

हरियाणा के मुख्य सचिव-DGP को नोटिस: आयोग ने 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी; जेल में बंद कैदी की पत्नी से इंस्पेक...

https://www.bhaskar.com/local/haryana/news/rape-case-with-wife-of-inmate-of-neemka-jail-report-to-be-given-in-6-weeks-130597602.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी किया है। आयोग ने फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद कैदी की पलवल जिले की रहने वाली पत्नी के साथ रेप के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। दोनों अधिकारियों को 6 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने इस मामले को लोक सेवकों के द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

SLSA सदस्य सचिव को भी दिए निर्देश

आयोग ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को भी इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। आयोग की तरफ से कहा गया है कि प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भी जेल में पीड़ित महिला के पति को लंबे समय तक कैद रखने मामले की जांच करनी होगी। साथ ही जांच रिपोर्ट 8 सप्ताह के भीतर आयोग में जमा कराना होगी। साथ ही आरोपी को मुफ्त न्यायिक सेवाओं का लाभ भी दिया जाए।

नीमका जेल (फाइल फोटो)

आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं

आयोग ने हरियाणा पुलिस से पूछा है कि आरोपी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की वर्तमान स्थिति पर जानकारी भी आयोग ने मांगी है। रिपोर्ट में अलग-अलग दंडनीय कानूनों के तहत लागू प्रावधानों का उल्लेख करने को भी कहा गया है।

क्या है पूरा मामला

आयोग ने मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच में तैनात एक इंस्पेक्टर ने महिला से जेल में बंद उसके पति की मदद करने का बहाना देकर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर ने महिला को ब्लैकमेल कर करीब 5.50 लाख रुपए भी वसूले। महिला की शिकायत पर सेक्टर 16 महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज किया गया।

फरार है आरोपी इंस्पेक्टर

केस दर्ज होने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है और वह वर्तमान में एचएसवीवी सेल में तैनात है। पुलिस आरोपी इंस्पेक्टर की पुलिस तलाश कर रही है।

पलवल की रहने वाली एक महिला को इंस्पेक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इतना ही नहीं आरोपी ने महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी लिए। इसके बाद उसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पैसे भी वसूले।

पति को छुड़वाने का भरोसा दिया

आरोपी ने महिला को आश्वासन दिया था कि वह जेल में बंद उसके पति को छुड़वाने और धाराएं कम करा देगा। महिला ने आरोपी इंस्पेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पहले साढ़े चार लाख रुपए लिए और फिर एक लाख रुपए बाद में लिए। पीड़ित महिला ने कहा कि उसका पति नीमका जेल में बंद है।

मेघालय फायरिंग को लेकर टीएमसी नेता साकेत गोखले ने एनएचआरसी में मामला दर्ज कराया

https://jantaserishta.com/local/assam/tmc-leader-saket-gokhale-files-case-in-nhrc-regarding-meghalaya-firing-1774326

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में असम सरकार के खिलाफ "असम वन द्वारा अकारण गोलीबारी और घातक बल के उपयोग की दुखद और चौंकाने वाली घटना" के संबंध में एक मामला दायर किया है। 22 नवंबर को मुखरो में मेघालय के निवासियों के खिलाफ गार्ड, जहां 6 लोग मारे गए थे, "नेता ने एक बयान में कहा। मामले में कहा गया है कि अकारण गोलीबारी में मारे गए मेघालय के पांच लोग निहत्थे थे और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे जो वन उपज पर अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। "असम वन अधिकारियों द्वारा निहत्थे व्यक्तियों के खिलाफ घातक बल का उपयोग अकारण और अवैध था। गोखले ने एक बयान में कहा, यह मामला तत्काल स्वतंत्र जांच के साथ-साथ असम सरकार को उन सभी असम बलों के कर्मियों को वापस लेने का आदेश देता है, जो वर्तमान में मेघालय के क्षेत्र में अवैध रूप से तैनात हैं।

इंस्पेक्टर ने जेल में बंद पति की मदद करने के बदले महिला से किया ...

https://udaipurkiran.in/hindi/inspector-rapes-woman-in-lieu-of-helping-jailed-husband-nhrc-issues-notice-to-haryana-chief-secretary/

हरियाणा (Haryana) के पलवल में एक क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ने जेल में बंद पति की मदद करने के बदले में एक महिला से बलात्कार किया. इस घटना की खबरों का संज्ञान लेते हुए मंगलवार (Tuesday) को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग(एनएचआरसी) ने हरियाणा (Haryana) के मुख्य सचिव और पुलिस (Police) महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और इस संबंध में छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है. आयोग के अनुसार यह घटना लोक सेवक द्वारा पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

आयोग ने नोटिस में मुख्य सचिव से पूछा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में तैयार दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं या नहीं? इसके साथ आयोग ने सचिव से राज्य में लोक सेवक द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पीड़न सहित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले एक वर्ष के आंकड़े की रिपोर्ट भी मांगी है.

आयोग ने पुलिस (Police) महानिदेशक को विशाखा मामले में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने और जांच शुरू करने में असमर्थता के लिए हरियाणा (Haryana) पुलिस (Police) के संस्थागत कार्यविधि की विफलता के कारणों के संबंध में की गई कार्रवाई सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. इसके साथ रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की मौजूदा स्थिति और गिरफ्तारी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. आयोग ने महानिदेशक से पूछा है कि पीड़ित महिला को मुआवजा दिया गया है या नहीं.

मीडिया (Media) रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पलवल की रहने वाली है. मई, 2020 के महीने में, उसके पति के खिलाफ कुछ विवाद को लेकर कुछ लोगों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया था. उसका पति नीमका जेल में बंद है. यह भी बताया गया है कि उस दौरान पीड़िता इंस्पेक्टर के संपर्क में आई, जिसने महिला से उसके पति को जेल से बाहर निकालने में मदद करने का वादा किया. यह भी बताया गया है कि इंस्पेक्टर ने उसका यौन शोषण करने से पहले 4 लाख रुपये और बाद में 1 लाख रुपये और ले लिए थे.

ORISSA POST, Bhubaneswar, 24.11.2022
Page No. 3, Size:(7.24)cms X (14.90)cms.

NHRC seeks report on Bolangir fatal fall

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, Nov 23: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought action-taken reports (ATRs) from the District Magistrate (DM) and Superintendent of Police of Bolangir over death of a man after falling off a joyride in Tureikela block of the district this November.

While hearing a plea filed by rights activist Radhakanta Tripathy, the NHRC asked the authorities to file the ATRs within four weeks.

Tripathy had informed the commission that Debraj Sahu of Tureikela block of Bolangir died after falling off a joyride in the locality during Kartik Purnima celebration November 8 this year.

He alleged that the mishap occurred due to the sheer negligence of the authorities.

ORISSA POST, Bhubaneswar, 24.11.2022
Page No. 7, Size:(19.66)cms X (7.46)cms.

Women, girls more at risk of being killed at home: Report

The report comes ahead of the International Day for the Elimination of Violence against Women November 25 and is a horrific reminder that atrocities against women and girls is one of the most pervasive human rights violations worldwide

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, Nov 23: A new study by UNODC and UN Women Wednesday showed that, on an average, more than five women or girls were killed every hour by someone in their own family in 2021.

Of all the women and girls intentionally killed last year, some 56 percent were killed by intimate partners or other family members (45,000 out of 81,000), showing that home is not a safe place for many women and girls. Meanwhile, 11 percent of all male homicides are perpetrated in the private sphere.

UN Women Executive Director Sima Bahous said: "Behind every femicide statistic is the story of an individual woman or girl who has been failed. These deaths are preventable - the tools and the knowledge to do so already exist."

"Women's rights organizations are already monitoring data and advocating for policy change and accountability. Now we need the concerted action across society that will fulfil women's and girls' right to feel and to be safe, at home, on the streets, and everywhere."

UNODC Executive Director Ghada Waly said: "No woman or girl should fear for her life because of who she is. To stop all forms of gender-related killings of women and girls, we need to count every victim, everywhere, and improve understanding of the risks and drivers of femicide so we can design better and more effective prevention and criminal justice responses."

REPRESENTATIONAL IMAGE

"UNODC is proud to launch the 2022 femicide study with UN Women to galvanize global action and salute the efforts of women's rights organizations around the world to end this crime."

This year's figures also show that over the past decade, the overall number of female homicides has remained largely unchanged, underscoring the urgency to prevent and respond to this scourge with stronger actions.

Even though these numbers are alarmingly high, the true scale of femicide may be much higher. Too many victims of femicide still go uncounted – given inconsistencies in definitions and criteria amongst countries, for roughly four in 10 women and girls killed intentionally in 2021, there is not enough information to identify them as femicide, especially for those killings happening in the public sphere.

As for regional disparities, while femicide is a problem that concerns every single country in the world, the report shows that in absolute numbers, Asia recorded the largest number of gender related killings in the private sphere in 2021, whereas women and girls were more at risk of being killed by their intimate partners or other family members in Africa.

In 2021, the rate of gender related killings in the private sphere was estimated at 2.5 per 100,000 female population in Africa, compared with 1.4 in the Americas, 1.2 in Oceania, 0.8 in Asia and 0.6 in Europe.

At the same time, the findings suggest that the onset of the Covid-19 pandemic in 2020 coincided with a significant increase in gender related killings in the private sphere in Northern America and to some extent in Western and Southern Europe.

However, gender-related killings, as well as other forms of violence against women and girls, are not inevitable.

STATESMAN, Bhubaneswar, 24.11.2022
Page No. 3, Size:(5.13)cms X (5.68)cms.

NHRC seeks ATR on joyride death

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 23 NOVEMBER:

The National Human Rights Commission sought Action Taken Reports (ATRs) from the Bolangir District Collector and Superintendent of Police over the electrocution of a man in a joyride swing.

Responding to a petition filed by Rights Activist and Supreme Court Advocate Radhakanta Tripathy, the NHRC issued notice calling for ATR without four weeks.

Debraj Sahu had fallen from a swing of a joyride at a fair in Tureikela block of Balangir district on 8 November last.

The petition alleged that the fatal accident could have been averted if the local authorities had issued a safety certificate after proper inspection of the joyride.

The petition sought for an inquiry and initiation of action against errant officials to check such fatal mishaps in future. The petition also sought for adequate compensation to the next of kin of the deceased.

The Statesman Thu, 24 November https://epaper.t

HARI BHOOMI, Rohtak, 24.11.2022
Page No. 2, Size:(6.93)cms X (16.97)cms.

बंदी की पत्नी से दुष्कर्म मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस

चंडीगढ़। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और को नोटिस जारी किया है। आयोग ने फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद कैदी की पलवल जिले की रहने वाली पत्नी के साथ रेप के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भी जेल में पीड़ि महिला के पति को लंबे समय तक कैद रखने मामले की जांच करनी होगी। आयोग ने हरियाणा पुलिस से पूछा है कि आरोपी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की वर्तमान स्थिति पर जानकारी भी आयोग ने मांगी है। इस्पेक्टर पर महिला से दुष्कर्म और लाखों रुपये हड़पने का आरोप है।

■ पुलिस इंस्पेक्टर पर संगीन आरोप